

ए.के. सीकरी से पहले, मुख्य न्यायाधीश और

राकेश कुमार जैन, जे.

जोगिंदर दत्त (मृत्यु) अपने \ एमएस के माध्यम से - अपीलकर्ता

बनाम

हंसराज (मृत्यु) अपने एलआरएस के माध्यम से

और अन्य-

उत्तरदाता

1984 का LPANo.91

अप्रैल 10,2013

हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 - धारा 14 - हिंदू महिला' संपत्ति का अधिकार अधिनियम, 1937 - धारा 3 (3) - नाथू राम की 1949 में निर्वसीयत मृत्यु हो गई, अपने पीछे तीन को पीछे छोड़ गए बेटे और विधवा जो सभी मृतक की संपत्ति के उत्तराधिकारी के हकदार थे। 1937 के अधिनियम की धारा 3 की शर्त-विधवा पर हस्तांतरित ब्याज सीमित था (हिंदू महिला' की संपत्ति), लेकिन उसे पुरुष मालिक के रूप में विभाजन का दावा करने का अधिकार था उसकी रुचि - विधवा उस संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गई जिसमें उसके पास था। 1956 के

अधिनियम के लागू होने के बाद सीमित ब्याज - मार्च में विधवा की मृत्यु हो गई। 1974 अपीलकर्ता को उसका हिस्सा वसीयत करना - विधवा की क्षमता को चुनौती अपनी संपत्ति के बारे में एक वसीयत बनाने के लिए - प्रतिवादियों का दावा था कि विधवा नहीं कर सकती थी। साबित करें कि उसके पास जो संपत्ति थी उसमें उसका हिस्सा उसके कब्जे में था। 1937 के अधिनियम के लागू होने पर सफल रहा - क्या धारा 14 लागू हो अगर महिला हिंदू वास्तविक, शारीरिक या रचनात्मक नहीं थी। धारा 14 (1) किसी भी संपत्ति पर लागू होगी, जो एक महिला हिंदू के स्वामित्व में है, भले ही वह उस संपत्ति के वास्तविक, भौतिक या रचनात्मक कब्जे में न हो।

आयोजित, कि अभिव्यक्ति का उपयोग " के पास" अभिव्यक्ति के बजाय " कब्जे में" का उद्देश्य इस अभिव्यक्ति के अर्थ को बढ़ाना था। यह आगे कहा गया है कि यह आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में जाना जाता है कि एक संपत्ति को किसी व्यक्ति के पास कहा जाता है, यदि वह मालिक है, भले ही वह कुछ समय के लिए, वास्तविक कब्जे या यहां तक कि रचनात्मक कब्जे से बाहर हो। धारा 14 (1) की भाषा पर, इसलिए, हम मानते हैं कि यह प्रावधान किसी भी संपत्ति पर लागू होगा, जो एक हिंदू महिला के स्वामित्व में है, भले ही वह उस संपत्ति के वास्तविक, भौतिक या रचनात्मक कब्जे में न हो।

(पैरा 13)

आगे कहा गया है कि यदि कोई हिंदू विधवा, जो अपने पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में अधिकार प्राप्त करती है, 1937 के अधिनियम के अनुसार, निर्वसीयत उसके पास मौजूद उसके हिस्से का पूर्ण स्वामी बन जाता है। यदि वह 1956 के अधिनियम के लागू होने के बाद जीवित रहती है तो मालिक होने के नाते और

यह आवश्यक नहीं है कि वह विवाद में संपत्ति में उसके हिस्से के वास्तविक भौतिक कब्जे में होना चाहिए क्योंकि यह सब आवश्यक है कि 1937 के अधिनियम के संदर्भ में उस संपत्ति में उसकी सीमित रुचि जारी है। 1956 के अधिनियम के लागू होने तक।

(पैरा 17)

अपीलकर्ताओं के लिए वकील श्रुति गुप्ता के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता।

एम.एल.सरीन, वरिष्ठ अधिवक्ता, नितिन सरीन और श्री संदीप बंसल के साथ, विज्ञापन वोकाट्स। उत्तरदाताओं।

राकेश कुमार जैन, जे.

(1) तथ्यों को ठीक से बताने के लिए, के संबंधों का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा, एक दूसरे के साथ पार्टियां, वर्तमान लिस में शामिल हैं, और इस उद्देश्य के लिए उनकी वंशावली तालिका है निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया: -

(2) यह सब जोगिंदर दत्त पुत्र नाथू रेन द्वारा दायर एक सिविल सूट से शुरू हुआ। भगवानदेवी पत्नी नाथू राम, मनोहर लाल पुत्र कांशी राम और अनंत राम पुत्र उत्तम चंद 12 संपत्तियों का विभाजन जिसमें जोगिंदर दत्त और भगवान देवी और प्रतिवादी संख्या 1 से 6 ने 1/3 वें हिस्से का दावा किया, जिसका अर्थ है कि दोनों ने 1/12 वें हिस्से का दावा किया; मनोहर लाल और प्रतिवादी संख्या 7 से 10 ने 1/3 हिस्से का दावा किया, जिसके अनुसार मनोहर लाल ने 1/6 वें हिस्से का दावा किया पत्नी; और अनंत राम और प्रतिवादी नंबर 1 ने 1/3 हिस्से का दावा किया, जिसके अनुसार अनंत राम 1/6 वें हिस्से का दावा कर रहा था। यहन वाद 3-1-01-1975 को डिक्री किया गया था और एक प्रारंभिक डिक्री को होल्ड करने का आदेश दिया गया था कि "यह आदेश दिया जाता है कि इस आशय का एक प्रारंभिक डिक्री कि योजना में उल्लिखित संपत्ति 'बी' पार्टियों का

संयुक्त है, हालांकि फर्म राय ब्रदर्स का व्यवसाय हंस राज प्रतिवादी का है। योजना 'ई' में उल्लिखित संपत्ति जो वर्तमान में हंसराज प्रतिवादी के कब्जे में है, क्या है? शिव दयाल, उत्तम चंद नाथू रानी (बेटा) (बेटा) अनंत राम गुरबक्स राय (बेटा) (बेटा) कांशी राम (बेटा) डीसीविंडर कुमार (बेटा) सुरिंदर कुमार मीरा हरीश प्रेमा चंदर (बेटा) (बेटी) आशा मीनाक्षी (बेटा) (बेटी) (बेटी) (बेटी) कांशी रानी, मनोहर लाल गोबिंद सरूप (बेटा) (बेटा) पार्टियों का संयुक्त। जहां तक संत राम को बेचे गए हिस्से का संबंध है, जैसा कि मद में उल्लेख किया गया है 'ई' और योजना एफ में उल्लिखित संपत्ति, यह साबित होता है कि ये संयुक्त नहीं हैं। कोई नहीं है। मद संख्या ए, सी, डी, जी, एच, आई, जे, के और लोफ वाद का मुख्य नोट। वादी नंबर 1 जोगिंदर दत्त प्रत्येक में 1/6 वें हिस्से का हकदार है। विवादित संपत्तियों की। मनोहर लाल वादी का उसमें 1/6 हिस्सा है, जबकि हिस्सा अनंत राम वादी 1/6 वें"।

(3) त्रि न्यायालय के निर्णय और डिक्री के विरुद्ध व्यथित, दो नियमित वादी द्वारा 1975 के आरएफए नंबर 309 और आरएफए नंबर 352 के साथ फर्स्टएपल्स दायर किए गए थे। प्रतिवादियों द्वारा 1975। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21.09.1983 के अपने आदेश द्वारा बर्खास्त कर दिया। 1975 के RFA No.309 और आंशिक रूप से 1975 के RFA No.352 की अनुमति दी, जैसा कि में दर्शाया गया है निर्णय।

(4) विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश से असंतुष्ट, उपर्युक्त 3 1984 की 91, 92 और 310 वाली अपीलें दायर की गई हैं जिन पर निर्णय लिया जा रहा है। इस सामान्य आदेश द्वारा एक साथ, यहां ऊपर बताए गए तथ्यों को ध्यान में रखते हुए।

(5) इस बात पर कोई विवाद नहीं है कि ट्रायल कोर्ट के समक्ष पक्षकारों की दलीलों पर विभाजन के लिए उक्त वाद में 13 मुद्दे बनाए गए थे, लेकिन अपीलों में विद्वान एकल न्यायाधीश ने केवल मुद्दे संख्या 2, 10 और 12 बी पर

विचारण के निष्कर्षों के रूप में प्रासंगिक होने पर चर्चा की अन्य मुद्दों पर अदालत को किसी भी पक्ष द्वारा चुनौती नहीं दी गई थी।

(6) 12 गुण थे जिन्हें प्रत्येक शाखा द्वारा विभाजित किया जाना था। शिव दयाल प्रत्येक के 1/3 हिस्से का दावा करते हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह देखा गया है कि पार्टियों के बीच मुख्य विवाद 16.03.1969 की वसीयत (पूर्व पीआई 39) के संबंध में है। भगवान देवी द्वारा जोगिंदर दत्त के पक्ष में अपना हिस्सा वसीयत करते हुए। विवाद है, वसीयत के उचित निष्पादन के संबंध में नहीं बल्कि वसीयतकर्ता की क्षमता के संबंध में। वही विद्वान एकल न्यायाधीश ने विद्वान के निष्कर्ष को उलट दिया है। ट्रायल कोर्ट जिसने माना था कि श्रीमती भगवान देवी अपने मृत पति के उत्तराधिकारी बने थीं। नाथू राम अपने तीन बेटों के साथ, जिनकी मृत्यु 1949 में कहीं हो गई थी, और बाद में उनकी मृत्यु हो गई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (इसके बाद "अधिनियम के रूप में संदर्भित" के रूप में संदर्भित) के बल में (ख) यदि हां, तो वह 1956 के अधिनियम की धारा 14 के आधार पर अपने हिस्से की पूर्ण स्वामी बन गई। यह विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा यह देखा गया है कि सबसे पहले श्रीमती भगवान देवी नहीं थीं। विवाद में संपत्ति का कब्जा जो उसने वसीयत के माध्यम से वसीयत किया था और दूसरा अपने जीवन काल के दौरान, उन्होंने अपने तीन बेटों के खिलाफ रखरखाव के लिए फॉर्मा पॉप्रिस के रूप में मुकदमा दायर किया। जिसमें उसने दावा किया था कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं है और उस मुकदमे की डिक्री 1999 में हुई थी। उसका एहसान। इस संबंध में विद्वान एकल न्यायाधीश का निष्कर्ष इस प्रकार है: -

"पक्षों के लिए विद्वान वकील को सुनने के बाद, मैं विचार का हूँ। यह राय कि वसीयत प्रदर्श पी-139 दिनांक 16.03.1969 श्रीमती के रूप में अमान्य थी। फांसी के समय भगवान देवी के पास कोई संपत्ति नहीं थी। कहा वसीयत। यहां तक कि रिकॉर्ड पर रखी गई वसीयत की प्रति में भी कोई उल्लेख नहीं है। संपत्ति के किसी विशिष्ट हिस्से का जिसके कब्जे में वह थी और खुद को पूर्ण मालिक होने का

दावा कर सकता है। बल्कि उसमें यह कहा गया है कि जो भी संपत्ति विभाजन पर उसके हिस्से में आ सकती है जिसे दिया जा सकता है। उनका बेटा जोगिंदर दत्त जब से उनकी सेवा कर रहा था। इस प्रकार, यह काफी स्पष्ट है कि उसके पास रखरखाव के माध्यम से या तो कोई संपत्ति नहीं थी या अन्यथा अपने पति के उत्तराधिकार के कारण और इसलिए, का प्रश्न परिस्थितियों में कोई वसीयत बनाने का प्रश्न नहीं उठा। का दृष्टिकोण इस संबंध में ट्रायल कोर्ट गलत है। सिर्फ इसलिए कि वह अंदर आने के बाद मर गई हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के बल ने उसे उसका पूर्ण मालिक नहीं बनाया अपने पति नाथू राम की संपत्ति में 1/4 हिस्सा होने का आरोप लगाया। यह मानते हुए कि वह हिंदू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम के तहत सफल होने की हकदार थी, लेकिन तथ्य की बात के रूप में, वह कभी सफल नहीं हुई और उसने कभी भी ऐसा दावा नहीं किया वर्तमान मुकदमा दायर करने से पहले किसी भी समय उत्तराधिकार। इसके अलावा, वह थी किसी भी संपत्ति या उसके किसी हिस्से के कब्जे में नहीं है जो इसके बनने के लिए हिंदू की धारा 14 के प्रावधानों को लागू करके पूर्ण मालिक उत्तराधिकार अधिनियम। सेट्रावसेरावा का अनुपात जोगिंदर दत्त के विद्वान वकील द्वारा जिस मामले (सुप्रा) पर भरोसा किया गया है, उसमें कोई मामला नहीं है। वर्तमान आसानी के तथ्यों के लिए आवेदन। उक्त मामले में, विधवा थी अपने दत्तक पुत्र के माध्यम से कब्जे में होने के लिए आयोजित किया गया था जिसे गोद लिया गया था। संपाश्विक के उदाहरण पर अमान्य। जहां तक वर्तमान सहजता का संबंध है, तथ्य यह है कि श्रीमती भगवान देवी ने अपने तीन पुत्रों के विरुद्ध भरण-पोषण के लिए वाद दायर किया। स्पष्ट रूप से साबित होता है कि उसके पास कोई संपत्ति नहीं थी। के इस दृष्टिकोण में इस मामले में, इस संबंध में ट्रायल कोर्ट के फैसले को रद्द किया जा सकता है। वसीयत प्रदर्श पी-139 दिनांक 16.03.1969 को अमान्य माना जाता है। श्रीमती भगवान देवी को निर्वसीयत और उनके तीन बेटों यानी हंस राज की मृत्यु माना जाएगा, जोगिंदर दत्त और उनके तीसरे बेटे दिलबाग राय के तीन बच्चे, जिनकी पहले मृत्यु हो गई थी, एल/3 प्रत्येक के हिस्से में समान रूप से सफल होगा।“

(7) अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि नाथू राम की मृत्यु 1956 में हुई थी। दिसंबर 1949 जब 1937 का अधिनियम लागू था। हिंदू महिलाओं के संपत्ति के अधिकार अधिनियम, 1937 (इसके बाद "1937 का अधिनियम" के रूप में संदर्भित) 14.04.1937 से प्रभावी हुआ और इसका विस्तार इसकी धारा 1(2) के अनुसार भाग ख राज्यों को छोड़कर संपूर्ण भारत में किया गया है। यह इस पर लागू होता है कृषि के अलावा अन्य संपत्ति। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इसमें शामिल संपत्तियां वर्तमान एलआई सभी शहरी संपत्तियां हैं और उनमें से कोई भी शहर के किसी भी हिस्से में स्थित नहीं है। किसी भी पूर्ववर्ती भाग बी राज्य के क्षेत्र। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि धारा 3 के अनुसार 1937 का अधिनियम, जब एक हिंदू की मृत्यु निर्वसीयत हो जाती है, तो उसकी विधवा, अलग संपत्ति, के अधीन हो जाती है। उप-धारा (3) के प्रावधान, उस संपत्ति के हकदार होंगे जिसके संबंध में वह मर जाता है। एक बेटे के समान हिस्से के लिए वसीयत। 1937 के अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (3), हालांकि, यह प्रावधान करता है कि इस प्रावधान के तहत हिंदू विधवा पर कोई ब्याज हस्तांतरित होता है। धारा हिंदू महिला की संपत्ति के रूप में जाना जाने वाला सीमित हित होगा, बशर्ते कि उसे पुरुष मालिक के रूप में विभाजन का दावा करने का समान अधिकार होगा। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है, कि नाथू राम की विधवा भगवान देवी की मार्च 1974 में मृत्यु हो गई और वह एक पूर्ण मालिक बन गई। 1956 के अधिनियम की धारा 14 (1) के संदर्भ में उसकी संपत्ति का और निष्पादित करने के लिए सक्षम था। वसीयत का हिस्सा जो उसने वास्तव में अपने बेटे जोगिंदर दत्त के पक्ष में निष्पादित किया था। 16.03.1969 (Ex.P 139)। इसलिए, यह दावा किया जाता है कि विद्वान एकल द्वारा दर्ज की गई खोज न्यायाधीश कि भगवान देवी की निर्वसीयत मृत्यु हो गई और उनके तीन पुत्र यानी हंस राज, जोगिंदर दत्त और उनके तीसरे पुत्र दिलबाग राय के बच्चे जिनकी पहले मृत्यु हो गई थी, वे किस हिस्से के बराबर सफल होंगे? 1/3 प्रत्येक, स्पष्ट रूप से अवैध है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि विवादित संपत्ति के मालिक होने के लिए भगवान देवी की क्षमता के बारे में एकल न्यायाधीश को सीखा उसके द्वारा

वसीयत इस आधार पर की गई है कि यह साबित नहीं हुआ है कि वह उस समय विवादित संपत्ति जब 1956 का अधिनियम लागू हुआ था। मैं इस संबंध में, वह है। मंगई सिंह के मामलों में सुप्रीम कोर्ट के विभिन्न फैसलों पर भरोसा किया और अन्य बनाम श्रीमती रत्नो (मृत) उनके कानूनी प्रतिनिधियों द्वारा और एक अन्य (1), वड्डेबोयिना तुलसम्मा और अन्य बनाम वड्डेबोयिना सेशा रेड्डी (मृत) L.Rs (2), रानी काली (स्निट) बनाम चौधरी अजीत शंकर और अन्य (3), और 7 के मामलों में मद्रास उच्च न्यायालय के दो डिवीजन बेंच के निर्णय (4) और एम.वी.चोकालिंगम पिल्लई और अन्य बनाम अलानिलु पशु और अन्य (5)। उन्होंने प्रस्तुत किया है कि Ex.P41 के अनुसार, भगवान देवी, PW1 के रूप में पेश होने के दौरान, स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वह अपने पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में 1/4 वां हिस्सा रखती है, जिसका अर्थ है। इस प्रकार उसने यह स्वीकार नहीं किया कि उसके पति की मृत्यु के बाद, उसकी संपत्ति केवल विरासत में मिली थी। उसके तीन बेटों के द्वारा, उसके द्वारा नहीं। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि नाथू राम की विधवा होने के नाते, जो 1949 में मृत्यु हो गई जब 1937 का अधिनियम लागू था, वह उसके द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के रूप में सफल रही। उसी हिस्से में निर्वसीयत जिस हिस्से में उसके बेटे सफल हुए थे, उस पर सीमित ब्याज हो सकता है। समय जो 1956 के अधिनियम के लागू होने के बाद निरपेक्ष हो गया और उस मामले के लिए, भले ही उसने फॉर्मा कंगाली के रूप में रखरखाव के लिए सिविल सूट दायर किया हो, जिसमें आरोप लगाया गया हो कि उसने ऐसा नहीं किया। किसी भी संपत्ति के अधिकारी, यह उसे उस अधिकार से वंचित नहीं करेगा जो उसके अनुसार निहित है कानून।

(8) दूसरी ओर, जोगिन्दरदत्त के दावे का विरोध करते हुए, विद्वान वकील

उत्तरदाताओं के लिए, जो हंस राज पुत्र नाथू राम के एलआर होते हैं और चुनाव लड़ रहे हैं। यह मुकदमा इस तथ्य के कारण है कि अगर भगवान देवी को संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं मिलता है। नाथू राम द्वारा छोड़ी गई, तो नाथू राम की पूरी संपत्ति तीन में विभाजित हो जाएगी। भाग जो जोगिंदर दत्त, 1 आईएनएस राज

और दिजबाग राय के पास जाएंगे, 1/3 की सीमा तक प्रत्येक को हिस्सा दें, लेकिन यदि भगवान देवी को 1937 के अधिनियम के प्रावधानों के आधार पर 1/4 हिस्सा मिलता है और 1956 के अधिनियम और उक्त हिस्से को वसीयत करने की क्षमता थी, तो उसका 1/4 हिस्सा जाएगा जोगिंदर दत्त को जो नाथू राम की संपत्ति में 1/2 वां हिस्सा प्राप्त करेगा, जबकि हंस राज और दिलबाग राय को प्रत्येक को 1/4 हिस्सा मिलेगा, उसने प्रस्तुत किया है कि नाथू राम की मृत्यु हो गई। 05.12.1949 और उनकी मृत्यु के बाद, 24.12.1949 को तीन रेफरी द्वारा एक पुरस्कार दिया गया था जो न्यायालय का नियम बनाया गया था। इन कार्यवाहियों में, भगवान देवी को विशेष रूप से एक के रूप में शामिल किया गया था।(ग) द्वारा संचालित फर्मों में से एक से 60,000/- रुपये की राशि के साथ मुआवजा दिया गया था। नाथू राम के परिवार और बच्चों को "औलाद" शब्द का उपयोग करके प्रत्येक को 1/3 हिस्सा दिया गया था, जिसमें भगवान देवी शामिल नहीं हैं। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि यह पूरी तरह से गलत और गलत है, कि भगवान देवी को दी गई 60,000/- रुपये की राशि केवल संबंधित राशि के रूप में अलग थी। फर्म शिव दयाल उत्तम चंद की, बल्कि डिक्री Ex.P 136 का एक संयुक्त पठन होगा यह दर्शाता है कि भगवान देवी को उनके पूरे हिस्से के लिए एकमुश्त निपटान के रूप में 60,000/- रुपये दिए गए थे। संपत्ति में और एक फिन तक सीमित नहीं था। उन्होंने आगे कहा कि चूंकि भगवान देवी के अधिनियम के संदर्भ में सफल होने का आरोप लगाते हुए उसने जिस हिस्से का आरोप लगाया था, उसके कब्जे में नहीं पाया गया था। 1937 में, उसे 1956 के अधिनियम के संदर्भ में पूर्ण मालिक घोषित नहीं किया जा सकता था। जो उसे जोगिंदर दत्त के पक्ष में वसीयत निष्पादित करने के लिए सक्षम बना सकता है।

(9) डब्ल्यूसी ने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और इसमें रिकॉर्ड का अवलोकन किया है, शुभकामनाएँ।

(10) तथ्य ज्यादा विवाद में नहीं हैं क्योंकि नाथू राम की मृत्यु 1950 में हुई थी। 1949 में वे अपने पीछे अपने तीन बेटों और अपनी विधवा भगवान देवी को

भी छोड़ गए। भगवान देवी नाथू राम की विधवा अपने पति नाथू राम की संपत्ति के उत्तराधिकारी होने की हकदार थी। 1937 के अधिनियम की धारा 3 के संदर्भ में अपने तीन बेटों के साथ। यह भी विवाद में नहीं है कि उस पर हस्तांतरित ब्याज सीमित था जिसे मैं लिंडू महिला की संपत्ति के रूप में जाना जाता था, लेकिन उसे अधिकार था। विभाजन का दावा टियर हित के पुरुष मालिक के रूप में किया गया लेकिन मार्च 1974 में भगवान देवी की मृत्यु हो गई और 1974 में इस बीच, 1956 का अधिनियम लागू करने योग्य हो गया। यह भी विवाद में नहीं है कि आने के बाद 1956 के अधिनियम के लागू होने पर, भगवान देवी संपत्ति की पूर्ण मालिक बन गईं, जो पहले उसकी संपत्ति के रूप में जाना जाता था जिसमें धारा 3 के संदर्भ में उसकी सीमित रुचि थी, 1937 का अधिनियम।

(11) एकमात्र मुद्दा यह है कि क्या एक हिंदू महिला को कब्जे में होना चाहिए जिसकी संपत्ति वह 1956 के अधिनियम के अनुसार पूर्ण मालिक बन गई। मैं विवाद प्रतिवादियों द्वारा उठाया गया यह मामला यह था कि भगवान देवी यह साबित नहीं कर सकी कि वह अंदर थी। अपने हिस्से की संपत्ति का कब्जा जो वह अपने तीन बेटों के साथ सफल हुई थी। उनके पति की मृत्यु का समय जब 1937 का अधिनियम लागू था।

(12) विद्वान एकल न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय का उल्लेख करते हुए गुम्मलपुरा तिक्कीना माताडा कोट्टुरुस्वामी बनाम सेत्रा के मामले में वीरव्वा और अन्य (6) ने माना है कि उस मामले में विधवा को अंदर रखा गया था अपने दत्तक पुत्र के माध्यम से कब्जा, हालांकि, गोद लेने को अमान्य माना गया था। संपार्श्विक का उदाहरण, लेकिन वर्तमान मामले में, भगवान देवी ने स्वयं के लिए एक मुकदमा दायर किया था। अपने तीन बेटों के खिलाफ रखरखाव जिसमें उसने कहा था कि उसके पास कोई भी नहीं है, जायदाद।

(13) गुम्मलपुरा तिक्कीना मातादा में फैसले के बाद कोट्टुरुस्वामी का मामला (सुप्रा), मंगई सिंह और अन्य के मामले में निर्णय (सुप्रा) आया है जिसमें "द्वारा

स्वामित्व" शब्द आया है, जैसा कि अधिनियम की धारा 14 (1) में प्रयोग किया गया है। 1956, स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है। उक्त मामले में, वादी विधवा को बेदखल कर दिया गया था। 1956 के अधिनियम के लागू होने से पहले 1954 की एक वर्ष की अवधि के दौरान यह प्रश्न उठा था कि क्या वह 1956 के अधिनियम के लागू होने के बाद पूर्ण स्वामी घोषित किया जा सकता है। ये था निर्णय के पैरा 7 में माना गया कि विधायिका ने जानबूझकर "कोई भी" शब्द का उपयोग किया है। एक महिला हिंदू के पास संपत्ति है" और नहीं "एक महिला के कब्जे में कोई संपत्ति हिंदू"। यह आगे माना गया कि रचनात्मक कब्जा एक पट्टेदार के माध्यम से हो सकता है, बंधक, लाइसेंसधारी, आदि। अभिव्यक्ति के बजाय "के पास" अभिव्यक्ति का उपयोग "के कब्जे में" इस अभिव्यक्ति के अर्थ को बढ़ाने का इरादा था। इसे आगे आयोजित किया जाता है। यह आमतौर पर अंग्रेजी भाषा में जाना जाता है कि एक संपत्ति को एक के पास कहा जाता है। व्यक्ति, यदि वह मालिक है, भले ही वह कुछ समय के लिए वास्तविक कब्जे से बाहर हो सकता है या यहां तक कि रचनात्मक कब्जा। यह आगे कहा गया था कि "यह हमें प्रतीत होता है कि अभिव्यक्ति अधिनियम की धारा 14(1) में प्रयुक्त कानून में कब्जे के मामलों को भी शामिल करने का इरादा था, जहां भूमि एक महिला के लिए उतर सकती है। हिंदू और उसने वास्तव में उनमें प्रवेश नहीं किया है। यह निश्चित रूप से, अन्य मामलों को कवर करेगा वास्तविक या रचनात्मक कब्जा। धारा 14(1) की भाषा के संबंध में, हम मानते हैं कि यह प्रावधान किसी भी संपत्ति पर लागू होगा जो एक महिला हिंदू के स्वामित्व में है, भले ही वह उस संपत्ति के वास्तविक, भौतिक या रचनात्मक कब्जे में नहीं है।

(14) मंगल सिंह और अन्य के मामले (सुप्रा) में निर्णय फिर से था-वड्कबॉयन ए तुलसम्मा और अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा पुष्टि की गई (सुप्रा)। राम काली के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा ही विचार व्यक्त किया है। (सुप्रा) वड्डेबोयिना तुलसम्मा और अन्य मामले (सुप्रा) में निर्णय को मंजूरी देना।

(15) आईएनआर. नरसिम्हाचारी बनाम अंडालम्मल (मृत्यु) और अन्य का मामला (सुप्रा), मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने इस प्रश्न की जांच की है, क्या 1937

के अधिनियम के तहत एक हिंदू विधवा का वैधानिक अधिकार उसके बिना हैसंपत्ति पर भौतिक कब्जा और उसे मांगने के लिए भी बाध्य किए बिनाविभाजन, अधिनियम की धारा 14(1) के अर्थ के अंतर्गत एक पूर्ण संपत्ति में विस्तारित होता है। 1956. इस प्रश्न का उत्तर निम्नलिखित आशय से सकारात्मक दिया गया।

“सुप्रीम कोर्ट और हमारे द्वारा बनाए गए कानून की व्याख्या का शुद्ध परिणाम कोर्ट का मानना है कि हिंदू विधवा के लिए यह जरूरी नहीं है कि वह इसके तहत अधिकारों का हकदार हो 1937 अधिनियम विभाजन की मांग करके या उसके लिए मुकदमा दायर करके विभाजन की मांग करता है उद्देश्य। 1937 अधिनियम के तहत संपत्ति रखने का उसका अधिकार या अधिकारकी धारा 14(1) के उदार एवं विस्तृत आयाम के कारण स्वयं को विस्तारित करता है 1956 अधिनियम।”

(16) पूर्वोक्त दृष्टिकोण को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा आगे दोहराया गया है, एम.वी.चोकलिंगम पिल्लई और अन्य का मामला (सुप्रा)।

(17) इस प्रकार उपरोक्त कानूनी स्थिति से यह बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि कोई हिन्दू है विधवा, जो बिना वसीयत के मरकर अपने पति द्वारा छोड़ी गई संपत्ति में अधिकार प्राप्त करती है 1937 के अधिनियम के अनुसार, यदि वह स्वामी है तो वह अपने हिस्से की पूर्ण स्वामी बन जाती है। 1956 के अधिनियम के लागू होने के बाद जीवित है और यह आवश्यक नहीं है कि वह अंदर रहे विवादग्रस्त संपत्ति में उसके हिस्से का वास्तविक भौतिक कब्जा यह सब आवश्यक है कि संपत्ति में उसकी सीमित रुचि जो शर्तों के अनुसार उसे सौंपी गई थी, 1937 का अधिनियम 1956 के अधिनियम के लागू होने तक जारी रहता है।

(18) इस प्रकार उपरोक्त चर्चा के परिप्रेक्ष्य में विद्वानों द्वारा जो निष्कर्ष रिकार्ड किया गया एकल न्यायाधीश ने कहा कि क्योंकि जिस समय भगवान देवी अपने हिस्से पर काबिज नहीं थीं, मार्च 1974 में उनकी मृत्यु हो गई, उनके पास उक्त हिस्से को प्राप्त करने की कोई योग्यता नहीं थी, इसे उलट दिया गया है और विद्वान ट्रायल कोर्ट की बात को बरकरार रखा गया है।

(19)जहां तक भगवान देवी द्वारा अपने खिलाफ भरण-पोषण का मुकदमा दायर करने का सवाल है।फॉर्मा पौप्रिस के पुत्रों के पास किसी भी संपत्ति का कब्जा नहीं होने से वह अपने अधिकारों से वंचित नहीं होती है।विवादग्रस्त संपत्ति में, जो 1937 के अधिनियम के बजाय कानून के कार्यान्वयन के लिए आया है और 1956 का अधिनियम। यहां उत्तरदाताओं का मामला यह नहीं है कि भगवान देवी का संबंध था।किसी भी समय उसके अधिकार की जांच की गई और उसके लिए विद्वान वकील द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया।प्रतिवादी ने कहा कि उसका दावा रुपये के भुगतान के आधार पर तय किया गया था। 60,000/- स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वह रकम उसे एक फर्म का हिसाब-किताब निपटाते समय नहीं बल्कि हिसाब-किताब करते समय दी गई थी।विवाद में संपत्ति में पार्टियों का हिस्सा जो नाथू के "औलाद" को दिया गया था।राम जिसमें से भगवान देवी को बाहर नहीं किया जा सकता क्योंकि "औलाद" शब्द का प्रयोग किया गया था।यहां सामान्य अर्थ में जिसमें भगवान देवी भी शामिल हैं, अन्यथा ऐसा होता रेफरी का इरादा केवल बेटों को संपत्ति देने का था, शब्द "लड़के" या "पुत्र"इस्तेमाल किया जा सकता था। ट्रायल कोर्ट ने ठीक ही कहा है कि "औलाद" शब्द का इस्तेमाल किया गया था।सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है जिसमें भगवान देवी भी शामिल हैं।

(20) जहां तक बिंदु "ई" पर उल्लिखित संपत्ति की संयुक्तता का संबंध है,अपीलकर्ताओं के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया है कि विद्वान ट्रायल कोर्ट ने इसके पैरा 14 में कहा है।निर्णय, यह मानता है कि संपत्ति "ई" पार्टियों का संयुक्त है जिसकी पुष्टि की गई है।एकल न्यायाधीश ने टिप्पणी करते हुए कहा कि "हंस राज प्रतिवादी के लिए विद्वान वकील ने कहा है।तर्क दिया गया कि आइटम 'बी' और एल ई' में संपत्तियां पार्टियों की संयुक्त संपत्ति नहीं हैं।ट्रायल कोर्ट ने इस संबंध में पुरस्कार प्रदर्शनी पी-37/1 पर गलत भरोसा किया है" और समापन कि "इस प्रकार, प्रतिवादी हंस राज की ओर से उस संपत्ति पर सफलतापूर्वक बहस नहीं की जा सकी आइटम 'ई' संयुक्त नहीं था।पार्टियों की संपत्ति" और "संपत्ति एल बी' के संबंध में भी यही स्थिति है, का निष्कर्ष इस संबंध में ट्रायल कोर्ट को प्रतिवादी की ओर से सफलतापूर्वक चुनौती नहीं दी जा सकी-अपीलकर्ता हंस राज"

(21) इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने यह प्रस्तुत किया है। 1984 के एलपीए नंबर 91 में अपील के आधार के पैरा 4 में यह दलील दी गई है कि यह संपत्ति है। पार्टियों का संयुक्त नहीं है और यदि उन्होंने उस समय संपत्ति 'ई' पर अपना दावा छोड़ने का विकल्प चुना है। वर्तमान अपील दायर करने के मामले में, उन्हें उस रुख का लाभ नहीं दिया जा सकता जो उन्होंने इसमें अपनाया था नीचे की अदालतें। आगे यह भी कहा गया है कि उन्हें संपत्ति 'एफ' से कोई सरोकार नहीं है। जैसा कि संपत्ति 'बी' का संबंध है, वही राय ब्रदर्स फर्म के पास है।

(22) पक्षों के विद्वान वकील को सुनने के बाद, हम सुविचारित राय पर हैं तथ्य का निष्कर्ष विद्वान ट्रायल कोर्ट के साथ-साथ विद्वान द्वारा भी दर्ज किया गया है। एकल न्यायाधीश ने संपत्ति की संयुक्त कंपनी के बारे में 'ई' में सूचीबद्ध किया है जिसे केवल हिलाया नहीं जा सकता है। इस तथ्य के कारण कि अपील के आधारों में संयुक्त न होने का गलत उल्लेख किया गया है, जैसा कि अपीलकर्ताओं के वकील ने कहा है।

(23) कोई अन्य मुद्दा नहीं उठाया गया है।

(24) अलग होने से पहले, यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि एक आवेदन पत्र जिसमें सी.एम.2013 की संख्या 1844-एलपीए को रिकॉर्ड में लाने के लिए 1984 की एलपीए संख्या 91 में दायर किया गया है। अतिरिक्त साक्ष्य के रूप में निर्णय दिनांक 27.09.1983। हालाँकि, हमारी खोज को ध्यान में रखते हुए दर्ज किया गया। 1937 के अधिनियम और अधिनियम के संदर्भ में भगवान देवी के कानूनी अधिकारों के संबंध में 1956, सर्वोच्च न्यायालय के विभिन्न निर्णयों द्वारा समर्थित, हमें अनुमति देने का कोई कारण नहीं मिलता इस स्तर पर यह एप्लिकेशन. अतः उक्त आवेदन खारिज किया जाता है।

(25) उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, तीनों अपीलें स्वीकार की जाती हैं और विद्वान एकल न्यायाधीश का आदेश अपास्त किया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मनीषा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

बहादुरगढ़, हरियाणा